



कॉर्पोरेट सेक्टर में मुकाम

कैसे लें प्रवेश

दसवीं के बाद ही लॉ की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। कई यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों में पांच वर्षीय बीए एलएलबी कोर्स कराया जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स के बाद इस क्षेत्र में कैरियर शुरू कर सकते हैं। एंट्रेस एग्जाम में बैठने के लिए दसवीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। देश के विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और स्कूल में एडमिशन 'कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी)' के माध्यम से होता है। अन्य संस्थान लॉ कोर्स के लिए अलग-अलग एंट्रेस एग्जाम्स आयोजित करते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में आमतौर पर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहां दाखिले की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

देश में कोर्ट बेशक कम हों, लेकिन मुकदमों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए अच्छे वकीलों की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। देश का कानून इतना व्यापक है कि स्पेशलाइजेशन की जरूरत बढ़ जाती है। इस तरह के स्पेशलाइजेशन की मेडिकल क्षेत्र से तुलना की जा सकती है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र के कानून के विशेषज्ञ के रूप में पहचान बना सकते हैं। यह क्षेत्र एडमिनिस्ट्रिटिव लॉ, कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ, इन्वॉयन्मेंटल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ आदि में से कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की बात करें, तो इसका क्षेत्र भी काफी व्यापक होता जा रहा है।

कैसे बन सकते हैं कॉर्पोरेट लॉयर

यह लीगल क्षेत्र का उभरता स्वरूप है। बड़े बिजनेस घराने और सरकारी विभागों को भी कई जटिल कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें हल करने के लिए कॉर्पोरेट लॉयर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनका काम कंपनी के संचालन में कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कंपनी से जुड़े मुकदमों की पैरवी करना, कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना आदि होता है। कॉर्पोरेट कंपनियों में मिलनेवाले आकर्षक वेतन के चलते युवा इस तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं।

क्या होता है काम

कंपनी को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सरकारी नियमों के अलावा कंपनियां अपने कर्मचारियों, उपभोक्ता या एंजोसिएट्स के लिए भी नियम बनाती हैं। ऐसे ही नियमों की गुंथियों को समझने और उनकी प्राथमिकताओं को पूरा करने का भार कॉर्पोरेट लॉ के जानकारों का होता है। कॉर्पोरेट लॉ फर्म अपने ग्राहक की टैक्स प्लानिंग से लेकर, कर्मियों, सहयोगियों, शेयरधारकों और यहां तक कि किरायों एवं समझौतों की संपूर्ण रूपरेखा बनाते हैं। कॉर्पोरेट लॉ फर्म किसी भी कंपनी की रीड होती है, जिसके द्वारा किये गये काम से ही कंपनी की वार्षिक आमदनी और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है।

किन क्षेत्रों में होती है इसकी भूमिका

कंपनी के टैक्सों का आकलन और निष्पादन, नये संस्थानों के गठन की संरचना, लाइसेंस समझौता बनाना, बौद्धिक संपत्तियों को संरक्षित करना, शेयरधारकों के लिए नियम बनाना, विक्रय और वितरक समझौते की रूपरेखा तैयार करना, ट्रेड मार्क और कॉपीराइट नियमों का निष्पादन करना, कर्मियों के लिए कंपनी अधिनियमों के अनुरूप नियम बनाना, संयुक्त या किसी भी प्रकार के उपक्रम की संरचना, नये व्यवसायों के लिए लाभ-हानि की सलाह देना वगैरह कॉर्पोरेट लॉयर के कामों में शामिल है।



लॉ की एक अहम शाखा है कॉर्पोरेट लॉ। इसके जरिये विद्यार्थी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। यह कोर्स पूरा करने के बाद बेहतरीन कैरियर विकल्प के साथ ही अच्छे वेतन की भी संभावना है। अगर आपमें अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता है और चुनौतियों को स्वीकार करने में आपको मजा आता है, तो आप कानून के एक्सपर्ट बन कर कैरियर में नयी ऊंचाई छू सकते हैं। पारंपरिक वकील और न्यायिक सेवाओं के अलावा अब कॉर्पोरेट लॉयर बन कर भी शानदार कैरियर बनाया जा सकता है। कैसे लें इस क्षेत्र में दाखिला और कैसे छुएं ऊंचाइयों को, सबके बारे में जानें विस्तार से।

पृथ्वी के गर्भ को समझने का मौका सीस्मोलॉजी

भूकंप विज्ञान का क्षेत्र काफी नया है। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से प्रगति की है। कई युवा साथी इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यह क्षेत्र केवल आपदा या उसके बाद के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान में किसी भी भवन के निर्माणकार्य से पूर्व उसे भूकंपरोधी बनाने के लिए भी कार्य करता है।

समझें पर्सनालिटी के मायने

पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को निखारने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि असल में पर्सनालिटी का अर्थ होता क्या है? समझें कि पर्सनालिटी ऊपरी नहीं, अंदरूनी होती है।



अकसर लोगों को यह कहते सुना जाता है कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या खराब। आखिर क्या है पर्सनालिटी? क्या सही मायनों में हम इस शब्द के व्यापक रूप को समझ पाए हैं?

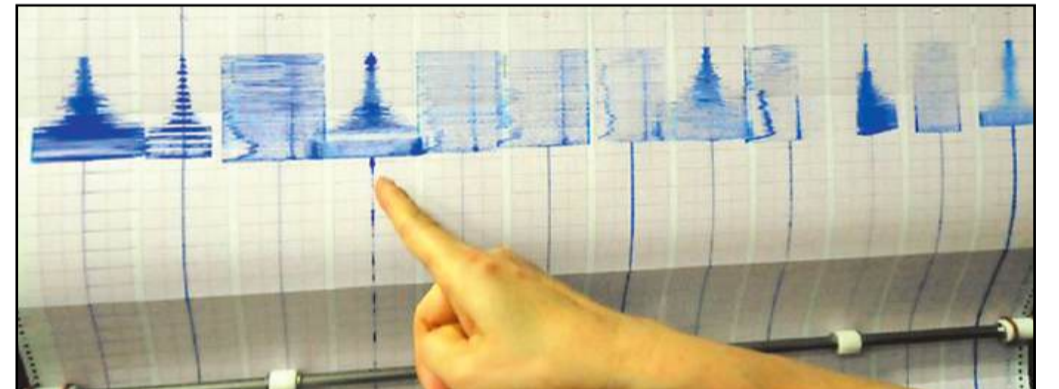
पर्सनालिटी को अकसर लोग शारीरिक आकर्षण या सुंदरता से जोड़ कर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस शब्द के व्यापक रूप को नहीं समझते। पर्सनालिटी शब्द, लैटिन शब्द पर्सोना से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है मास्क। इस शब्द का उपयोग रोमन के लोग थियेटर में काम करने के लिए और अलग-अलग किरदार निभाने के लिए करते थे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पर्सनालिटी वही है, जैसा हम देखते हैं या दूसरों को नजर आते हैं, लेकिन पर्सनालिटी की यह परिभाषा बहुत ही संकुचित है। व्यक्तित्व को सही रूप में इस परिभाषा से समझा जा सकता है -

पर्सनालिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से ही नहीं, बल्कि विचारों और व्यवहार से मिल कर बनती है। यह समाज में हमारे समायोजन और हमारे व्यवहार को भी निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनालिटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि सफल होने लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है। ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करें। साथ ही अपने आपको भी विकसित करें। शारीरिक रूप से सुंदर होना या बुद्धिमान होना व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू है। अच्छी पर्सनालिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना और अपनी मुद्रा व हाव-भाव को उसके अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। अपने साथियों से बेहतर बनने के बजाय कोशिश करें कि आप अपने आपमें बेहतर बनें।

दबाव और डर दो बहुत ही बड़े कारण हैं, जो पर्सनालिटी को पूरी तरह से निखारने नहीं देते। इसलिए अपने अंदर के डर को पहचानना और उससे मुक्त होने का प्रयास करना आवश्यक है। व्यक्तित्व में विचारों और व्यवहारों की भूमिका के साथ-साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नकारा नहीं जा सकता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ सिर्फ खूबसूरत चेहरे से नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा और रहन-सहन का ढंग भी है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से भी आंका जा सकता है कि वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों का किस प्रकार निर्वाह कर रहा है या उसमें कितना सफल है।

नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर पाएं विजय

अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पहली आवश्यकता है इसे सही तरीके से समझना। आप अकसर वही देखते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। अपनी नकारात्मक और कमतर समझने की भावना से दूर रहना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप देखने में आकर्षक नहीं हैं, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। इसका सटीक उदाहरण मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी जैसी शख्सियतें हैं। वे शारीरिक रूप से आकर्षित करनेवाले नहीं थे, लेकिन समाज के लिए इनका व्यक्तित्व एक मिसाल है। इन लोगों ने अपनी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पायी और खुद पर भरोसा किया। नकारात्मक भावनाओं और विचारों पर विजय पाने का उपाय है, खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा समझो और ऐसे लक्ष्य बनाओ, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं।



क्या है सिस्मोलॉजी

यह भूकंप और भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की अंतरंग अवस्था को समझने का विज्ञान है। यह विज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। भूकंप विज्ञान की शुरुआत 1880 के आसपास भूकंपलेखी उपकरण के आविष्कार के साथ हुई। जो विद्यार्थी इस विषय को लेकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें अर्थकेंद्र इंजीनियर कहा जाता है। अर्थकेंद्र इंजीनियरिंग यानी सिस्मोलॉजी के अध्ययन में धरती के भीतर होनेवाले कंपन यानी भूकंप के कारणों के बारे में जाना जाता है। साथ ही, इससे मानवीय जीवन को होनेवाले नुकसान के अलावा जान-माल और पर्यावरण को होनेवाले नुकसान का भी अध्ययन किया जाता है। भूकंप के कुछ सेकेंड बाद ही आखिर यह कैसे पता चल जाता है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर कितनी थी और इस भूकंप का केंद्र कहां स्थित था। इनकी जानकारी सिस्मोग्राफर की मदद से हो पाती है। भूकंप विज्ञान में केवल उसकी तीव्रता को नहीं मापा जाता। भूकंप आने के पूर्व और बाद की घटनाएं, पर्यावरण में बदलाव के अलावा किस प्रकार के भूकंप का जान-माल पर कैसा असर पड़ता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही, पृथ्वी के गर्भ में मौजूद खनिजों आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है।

योग्यता - भारत में अर्थकेंद्र इंजीनियरिंग की शिक्षा पोस्टग्रेजुएट स्तर पर उपलब्ध है, जिसमें छात्र मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमइ) / मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एमटेक) कर सकते हैं। इन कोर्स में ग्रेजुएट एपीटीयूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। इस विषय में पीएचडी भी कर सकते हैं।

चुनौतीपूर्ण है यह क्षेत्र

अगर आप सिस्मोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो यह भलीभांति समझ लें कि यह क्षेत्र आसान नहीं है। इसमें आप अधिकांश समय व्यस्त ही रहेंगे। हां, अगर आप उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो इस काम में मजा भी बहुत आयेगा। भूकंप से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के बाद प्रयोगशाला में उसका अध्ययन करना और उससे प्राप्त आंकड़ों से नयी चीजें सीखना, आपकी दिनचर्या में शामिल हो जायेगा। अर्थकेंद्र इंजीनियरिंग या सिस्मोलॉजी में पृथ्वी

के अंदर होनेवाली समस्त गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अर्थकेंद्र इंजीनियर इन जानकारीयों के आधार पर ही भूकंप के आशंकित क्षेत्रों, उसकी तीव्रता, पर्यावरण और जनसंख्या पर उसके प्रभाव आदि का आकलन करता है। इसके अन्य प्रमुख कार्यों में क्षेत्र विशेष और वहां आनेवाले भूकंपों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भवनों की डिजाइन बनानी होती है, जिससे भूकंप से नुकसान कम हो।

संभावनाएं हैं अपार

सिस्मोलॉजी एक ऐसा विषय है, जिसमें उच्च अध्ययन करनेवाले युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान की इस शाखा के तहत पृथ्वी, इसका पर्यावरण, इतिहास, खनिज आदि का अध्ययन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय में अध्ययन करनेवाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश-विदेश में खुल रहे भूकंप अध्ययन केंद्रों, शोध संस्थाओं, सर्वे कंपनियों आदि में काम करने के अवसर तो पर्याप्त संख्या में हैं ही, साथ ही यदि इस क्षेत्र में अच्छी योग्यता हासिल कर ली जाये, तो इस विषय को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का भी अवसर मिल सकता है। विदेशी विश्वविद्यालयों में भी इस विषय के जानकारों की आवश्यकता रहती है। विदेशी शोध संस्थाओं के साथ जुड़ना आय के लिहाज से अच्छा माना जाता है। एक अच्छी जानकारी रखनेवाले अर्थकेंद्र इंजीनियर का प्रारंभिक वेतन अमूमन 30 हजार रुपये प्रति माह तक होता है। कंपनी के कद के हिसाब से अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।



बांदीपोरा में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की समीक्षा, परियोजनाएं तेज करने के निर्देश



बांदीपोरा, 07 जुलाई। उपायुक्त बांदीपोरा इंडु कवल चिब ने आज मिनी सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैड्स के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में उपायुक्त ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के तहत कुल 30 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 15 कार्य ग्रामीण विकास विभाग, 6 कार्य लोक निर्माण विभाग, 3 कार्य युवा सेवा एवं खेल विभाग** तथा 1 कार्य नगर परिषद** द्वारा किए जा रहे हैं। अधिकांश कार्य या तो पूरे हो

चुके हैं अथवा प्रगति पर हैं, जबकि **5 कार्य अभी लंबित** हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों की नियमित निगरानी कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं का समय और क्रियान्वयन सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में सहायक आयुक्त विकास, मुख्य योजना अधिकारी, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण

विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिल्ली में सजेगा 'इंडी हाट 2026', गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, 07 जुलाई (हि.स.)। भारत की सदियों पुरानी कला, हथकरघा और हस्तशिल्प की अनुद्वी विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए देश की राजधानी में इंडी हाट 2026 का भव्य आयोजन होगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 10 से 19 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव का 13 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। वस्त्र मंत्रालय अनुसार यह आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत और जोकल फॉर लोकल अभियानों को एक नई उड़ान देगा। इस बार का इंडी हाट बेहद खास है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है।

यात्रियों की सुविधा एवं रोजगार सृजन हेतु जम्मू मंडल में एटीवीएम फेसिलीटेटर, एसटीबीए एवं वाईटीएसए के स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित

***जम्मू, 07 जुलाई।** यात्रियों को बेहतर एवं सुगम टिकट बुकिंग एजेंट योजना के अंतर्गत छोटे रेलवे स्टेशनों पर निजी एजेंट नियुक्त किए जाएंगे जो आम जनता को अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से टिकट उपलब्ध कराना और रेलवे टिकट काउंटरों पर काम का बोझ कम करना है। यह सुविधा मुख्य रूप से हस्त-4.5 और हस्त-6 श्रेणी के स्टेशनों पर लागू होगी। टिकट बिक्री पर एजेंट को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रतिशत में कमीशन प्रदान किया जाएगा।

यात्री टिकट सुविधा केंद्र रेलवे की पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना है। इसके अंतर्गत बाजारों में रेलवे टिकट काउंटर खोलने की अनुमति दी जाती है। इन केंद्रों पर यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे के नियमानुसार इन केंद्रों द्वारा यात्रियों से अतिरिक्त सेवा शुल्क भी लिया जा सकेगा। इस योजना में उन अनुभवी एजेंटों को प्राथमिकता से दी

फेसिलीटेटर भी तैनात किए जाते हैं। वहीं स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट योजना के अंतर्गत छोटे रेलवे स्टेशनों पर निजी एजेंट नियुक्त किए जाएंगे जो आम जनता को अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से टिकट उपलब्ध कराना और रेलवे टिकट काउंटरों पर काम का बोझ कम करना है। यह सुविधा मुख्य रूप से हस्त-4.5 और हस्त-6 श्रेणी के स्टेशनों पर लागू होगी। टिकट बिक्री पर एजेंट को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रतिशत में कमीशन प्रदान किया जाएगा।

यात्री टिकट सुविधा केंद्र रेलवे की पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना है। इसके अंतर्गत बाजारों में रेलवे टिकट काउंटर खोलने की अनुमति दी जाती है। इन केंद्रों पर यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे के नियमानुसार इन केंद्रों द्वारा यात्रियों से अतिरिक्त सेवा शुल्क भी लिया जा सकेगा। इस योजना में उन अनुभवी एजेंटों को प्राथमिकता से दी



जाएगी।

नए जम्मू मंडल के गठन के बाद यात्रियों को स्थानीय स्तर पर तेज एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिकता है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट और यात्री टिकट सुविधा केंद्र के माध्यम से टिकटिंग का काम और अधिक सुचारु रूप से संचालित होगा तथा कर्मचारियों की कमी की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि टिकटिंग का भार इन एजेंसियों एवं मशीनों पर बंट जाएगा। यह पहल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जम्मू श्री उचित सिंघल के नेतृत्व में जम्मू मंडल द्वारा डिजिटल इंडिया को

बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे नकद रहित लेन-देन और तकनीक आधारित टिकटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इन योजनाओं से स्थानीय युवाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं अनुभवी एजेंटों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू श्री उचित सिंघल ने कहा कि दुष्कृत्या जम्मू मंडल यात्रियों की सेवा और विकास दोनों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एटीवीएम, एसटीबीए और वाईटीएसए केवल टिकट बिक्री के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये जनता और रेलवे के बीच विश्वास का सेतु हैं। हमारा संकल्प है कि जम्मू मंडल के प्रत्येक यात्री को चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या दूर-दराज के गांव में, न्यूनतम समय में अधिकतम सुविधा उपलब्ध हो। इन योजनाओं के माध्यम से हम टिकटिंग को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहते हैं, ताकि यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिले और उन्हें घर के पास ही सम्मानजनक सेवा प्राप्त हो।

सावधान-कटुआ में एटीएम पर कार्ड बदलने वाला गिरोह सक्रिय, कार्ड बदलकर 67 हजार उड़ाए

कटुआ 07 जुलाई (हि.स.)। कटुआ शहर के रेलवे रोड क्षेत्र में एक बार फिर एटीएम कार्ड बदलकर टगी करने का मामला सामने आया है। ताजा घटना रेलवे रोड स्थित पीएनबी के एटीएम से जुड़ी है जहां एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल लिया गया और उसके खाते से कुल 67 हजार रुपये निकाल लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे रोड निवासी रामपाल सिंह ऐसे निकालने के लिए पीएनबी के एटीएम में गए थे। इस दौरान उन्हें मशीन से पैसे निकालने में दिक्कत आ रही थी। तभी वहां मौजूद कुछ अज्ञात युवकों ने उनकी मदद करने का बहाना किया और बड़ी चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। इसके बाद ठगों ने अलग-अलग स्थानों से पैसे निकाल लिए। पहले करीब 60 हजार रुपये निकाले गए जबकि बाद में कालीबाड़ी क्षेत्र के एक एटीएम से 7 हजार रुपये और निकाल लिए। जब पैसे निकलने के मैसेज रामपाल सिंह के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए तो उनके परिवार के लोग हैरान रह गए। पीड़ित के बेटे सत्यम ने बताया कि घटना के लगभग डेढ़ घंटे के भीतर ही साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई साथ ही संबंधित पुलिस चेकी में भी मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बैंक से एटीएम की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग भी की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में एक दंपति के साथ इसी तरह की टगी की वारदात हो चुकी है जिसमें उनके खाते से करीब 20 से 22 हजार रुपये निकाले गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे रोड क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर लोग रहते हैं जिन्हें इस तरह के गिरोह आसानी से निशाना बना रहे हैं।

जावेद राणा ने सुनीं जन समस्याएं, त्वरित समाधान का दिया भरोसा

श्रीनगर, 07 जुलाई (हि.स.)। जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मंगलवार को श्रीनगर में विभिन्न जन प्रतिनिधिमंडलों और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे और विकास संबंधी मांगें रखीं तथा शीघ्र समाधान की अपील की। मंत्री ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि प्रत्येक वास्तविक समस्या का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय बनाकर जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मंत्री ने कहा कि जनता से नियमित संचार ही सुशासन की कुंजी है और सरकार आम लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

7 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

कटुआ, 07 जुलाई (हि.स.)। कटुआ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिलावर क्षेत्र में 7 वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसएसपी कटुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भुषण कुमार पुत्र पुन्नू राम निवासी धार दुम्रू तहसील बसोहली जिला कटुआ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में थाना बिलावर में एफआईआर नंबर 68/2019 धारा 380/511 आरपीसी के तहत मामला दर्ज था और वह लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस थाना बिलावर की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की।

टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए श्रम एवं रोजगार और रक्षा के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक

नई दिल्ली, 07 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन में समन्वय मजबूत बनाने और समग्र सरकारी दृष्टिकोण द्वारा इसमें तेजी लाने के लिए मंगलवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक की। प्रगति समीक्षा बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदलने के लिए भारत की युवा शक्ति के इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा टीबी (तपेदिक) उन्मूलन के लिए सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक मंत्रालय, संस्था और हितधारकों द्वारा उनकी क्षमताओं और पहुंच के माध्यम से योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि

मिशन युवा के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की समीक्षा, समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश



****अनंतनाग, 07 जुलाई।** अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त अनंतनाग विकास अहलावत ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में मिशन युवा के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में कार्यक्रम के विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की प्रगति का आकलन किया गया।

बैठक में आउटपुट ट्रेकिंग, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सॉल्यूडि जारी करने, ओएनडीसी

पर लाभार्थियों के पंजीकरण तथा **उदम जागृति 5.0** कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की रिश्थि का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से ओएनडीसी पर लाभार्थियों का पंजीकरण तेज करने तथा मिशन युवा के तहत स्वयं सहायता समूहों के अधिक से अधिक आवेदन जुटाने पर जोर दिया, ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।

बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनआरएलएम), रोजगार अधिकारी, करियर काउंसलिंग अधिकारी, डीईसीसी, एसबीडीयू एवं बीएचडी के सदस्य तथा मिशन युवा के प्रेरक उपस्थित रहे।

पीएम पैकेज कर्मचारियों के ट्रांजिट आवास परियोजना का उपायुक्त ने लिया जायजा

बडगाम, 07 जुलाई। उपायुक्त बडगाम अशर आमिर खान ने आज काकनमरान का दौरा कर जिले के पीएम पैकेज एवं प्रवासी कर्मचारियों के लिए निर्माणधीन ट्रांजिट आवास परियोजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। यह परियोजना पीएम पैकेज कर्मचारियों को आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसके तहत 12 आवासीय ब्लॉकों में कुल 192 यूनिट, एक सामुदायिक भवन, एक छात्रावास (ऑरमेंटी) तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। दौरे के दौरान उपायुक्त के साथ संयुक्त निदेशक योजना, बडगाम, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण एवं जल शक्ति मंडल, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विकास विभाग, राहत विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

शांतिप्यां में दो लश्कर आतंकियों की चौथे दिन भी तलाश

शांतिप्यां, 07 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के शांतिप्यां जिले में प्रतिबंधित लश्कर-आ-तैयबा के दो स्थानीय आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की कई टुकड़ियों की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार शाम तक चार गांवों में तलाशी पूरी कर ली थी।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य इंजीनियर/पुल/कार्यशाळा, उत्तर रेलवे, जालंधर छावनी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से, ओपन ई-टेंडर को एकल पैकेट सिस्टम के तहत निमित्त किया गया है।

क्रम सं. 1: निविदा सं. : OT-18-JRC-2026

कार्य का विवरण : स्वीकृत इंडिया के अनुसार 3.05 मीटर से 12.20 मीटर लंबाई की प्री-स्ट्रेस कंक्रीट (PSC) स्लैबों की डलाई, ग्रेज वर्कशॉप, जालंधर कैंट के PSC यार्ड में करना।

अनुमानित लागत : ₹. 3,22,92,668.52

घरोहर राशि : ₹. 6,45,900.00

सुलने की तिथि : 27.07.2026

IREPS पर बोली लगाने की तिथि : 13.07.2026 से 27.07.2026

निविदा फार्म की लागत रुपये : 0

कार्य समापन का समय : 12 महीने

निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने के लिए दिनांक और समय : प्रत्येक के खिलाफ दिखाए गए तिथियों पर 15:00 बजे तक और उरपी समय 15:00 बजे के बाद।

वेबसाइट विवरण/पुल/निविदा का पूरा विवरण देखा जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है : विस्तृत ई-निविदा सूचना उत्तर रेलवे वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है और निविदा दर्तावेज www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

सं. : 80-W/30/Bridges/Invitation दिनांक: 04.07.2026 2302/2026

ग्राहकों की सेवा में मुकाम के उम्मी

UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD
(R&B) ELECTRIC DIVISION JAMMU
NOTICE INVITING TENDER

e-NIT No.EDJ/ 52 of2026-2027 Dated 07-07-2026

For and on behalf of the Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir e-tenders are invited on nion Territory of J&K, CPWD, Railways, MES and other State/Central Governments for each of the following works:-

S. No	Name of Work	Name of Division	Estimatl ed Cost ('in lacs)	Cost of docume nt ('in ')	Earnest Money ('in ')	Time Allowed for comple-tion	Time and date of opening of tender	Class of Contractor
1	Supply Installation testing and commissioning of IP CCTV system at Directorate Office State Motor Garages New Plot Jammu.	PWD (R&B) Electric Division Jammu	30.66	600/-	61320/-	60 Days	17-07-2026 At or after (12:00 A.N	"A" Class Electrical Contractor/OEM Or their Authorized-Distributor/Dealers/System Integrators/Firms Fulfilling Eligibility Criteria.

The Bidding documents Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, bill of quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the departmental website <http://jktenders.gov.in> as per below schedule.

1	Date of Issue of Tender Notice	07-07-2026
2	Period of downloading of bidding documents	From 07-07-2026 to 16-07-2026, 4:00 P.M
3	Bid submission Start Date	07-07-2026
4	Bid Submission End Date	16-07-2026 up to 4:00 P.M
5	Pre Bid Meeting Date	xxxx at or after xxxx in the Office of the Executive Engineer PWD (R&B) Electric Division Jammu
5	Date & time of opening of Technical Bids (Online)	17-07-2026 at or after 12:00 A.N in the Office of the Executive Engineer PWD (R&B) Electric Division Jammu
6	Date & time of opening of Financial Bids (Online)	To be notified after technical bid evaluation is completed

- Position of Administrative Approval = Accorded
- Position of Technical Sanction = Accorded
- Position of Funds = Awaited.

- Bids must be accompanied with cost of Tender document in shape of e-challan through Treasury indicating Treasury Voucher No. & date and also indicating the name of work and NIT No. duly crediting to 0059 (Revenue) favouring Executive Engineer PWD (R&B) Electric Division Jammu. uploading a copy of treasury challan/receipt. The original instruments in respect of cost of documents, and relevant documents of L1 be submitted to the Executive Engineer PWD (R&B) Electric Division Jammu at the time of allotment.
- Bid Security Declaration should be kept in the Bid documents as per tendered.
- The date and time of opening of Financial-Bids shall be notified on Web Site www.jktenders.gov.in and conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-mail address. The Financial-bids of Responsive bidders shall be opened online in the Office of the Executive Engineer PWD (R&B) Electric Division Jammu. The date for same shall be intimated separately.
- The bids for the work shall remain valid for a period of 120 days from the date of opening of Technical bids.
- The earnest money shall be forfeited, if :-
a) Any bidder/tenderer withdraws his bid/tender during the period of bid validity or makes any modifications in the terms and conditions of the bid.
b) Failure of Successful bidder to furnish the required performance security within specified time period after issue of letter of acceptance.
c) The L-1 Bidder shall have to deposit e-stamp paper of Rs. 100/- alongwith Agreement Form (As per Annexure "B") and other relevant documents with 7 days after issuance of allotment.
- Instruction to bidders regarding e-tendering process.
6.1 Bidders are advised to download bid submission manual from the "Downloads" option as well as from "Bidders Manual Kit" on website www.jktenders.gov.in to acquaint bid submission process.
6.2 To participate in bidding process, bidders have to get 'Digital Signature Certificate (DSC)' as per Information Technology Act-2000. Bidders can get digital certificate from any approved vendors.
6.3. The bidders have to submit their bids online in electronic format with digital Signature. No financial bid will be accepted in physical form.
6.4. Bids will be opened online as per time schedule mentioned above.
6.5. Bidders must ensure to upload scanned copy of all necessary documents mentioned in NIT and SBD with technical bid online.
6.6 That the Bidder is not a PRI member.
6.7 All the information and documents submitted by me are true and correct to the best of my knowledge and if found wrong the bidder shall be liable to face legal proceedings.
No :- EDJ/9385-94 Dated :-07-07-2026

Sd/-
Executive Engineer
PWD (R&B) Electric Division
Jammu

DIP/J-5238/26
Dtd: 7-7-2026

संपादकीय

अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई

अवैध घुसपैठ अब केवल सीमा प्रबंधन का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन, आर्थिक संसाधनों और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ी एक जटिल चुनौती बन चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का केंद्र सरकार का निर्णय इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित राष्ट्रीय रणनीति समय की आवश्यकता है।

हालांकि अवैध घुसपैठ देश के कई हिस्सों को प्रभावित करती है, लेकिन जम्मू क्षेत्र लंबे समय से विशेष रूप से रोहिंग्या अवैध प्रवासियों की मौजूदगी के कारण चिंता का विषय रहा है। वर्षों के दौरान जम्मू शहर और आसपास के जिलों में इनके बड़े-बड़े ठिकाने विकसित हुए हैं। आधिकारिक एजेंसियों का कहना है कि कड़ी सीमा निगरानी और मजबूत खुफिया तंत्र के कारण नई घुसपैठ पर काफ़ी हद तक रोक लगी है, लेकिन हजारों अवैध प्रवासियों की लगातार मौजूदगी अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

यह समस्या केवल बिना अनुमति देश में प्रवेश तक सीमित नहीं है। अवैध प्रवासी अक्सर ऐसे संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जो सीमा पार कराने, आश्रय उपलब्ध कराने, परिवहन की व्यवस्था करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें समाज में घुलने-मिलने में मदद करते हैं। ऐसे नेटवर्क कानून के शासन को कमजोर करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इनकी मौजूदगी आंतरिक सतर्कता और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

वर्षों से सामने आई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कई अवैध प्रवासी पहचान पत्र बनाने, बैंक खाते खोलने और सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ लेने में सफल रहे। इससे सत्यापन प्रणाली की खामियां उजागर होती हैं और संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुछ व्यक्ति और संगठित गिरोह कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर अवैध बसावट से आर्थिक लाभ कमाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने और संवेदनशील सुरक्षा परिस्थितियों के कारण जम्मू में यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्षेत्र दशकों से आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ का सामना करता रहा है। ऐसे में बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों की मौजूदगी स्वाभाविक रूप से वैध सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून लागू करते समय वास्तविक भारतीय नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न हो।

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की बैठक अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक समान व्यवस्था विकसित करने, जहां लागू हो वहां निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को ध्वस्त करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसके लिए खुफिया एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बलों और वित्तीय जांच एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक होगा।

भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने का पूरा अधिकार ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। संवेदनशील परिस्थितियों में फंसे लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अवैध घुसपैठ और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई समान रूप से आवश्यक है। चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि उस समानांतर तंत्र को समाप्त करने की भी है जो अवैध गतिविधियों को संरक्षण और प्रोत्साहन देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कानून आधारित, समन्वित और निर्णायक कार्रवाई ही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मूल्य श्रृंखला का जुड़ाव- पीएम मित्र पार्क के जरिए कैसे भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की बदल रही है तस्वीर



श्री पबित्रा मार्गेरिटा

सदियों से, भारत की पहचान उसके परिधानों से गहराई से जुड़ी रही है। चाहे वह कश्मीर के पश्मीना की लंबे समय तक रहने वाली गर्माहट हो, असम के मृंगा सिल्क की सुनहरी चमक हो, तमिलनाडु की शाही काजीवरम साड़ियाँ हों, चंदेरी की बुनाई हो या सूरत के कारीगरों की कपड़ों पर मशहूर कारीगरी। आज भी यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, जो जीडीपीमें 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यह क्षेत्र45 मिलियन लोगों को सीधे तौर पर और 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। इससे ग्रामीण समुदायों को मजबूती मिलती है और देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का रास्ता खुलता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के एक साथ जुड़ी हुईव्यवस्था के उलट, भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग जगहों पर फैले हुए मॉडल के तौर पर विकसित हुई। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, कपड़े सिलने और निर्यात जैसी गतिविधियाँ अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, जिसका अर्थ था कि एक कपड़ा बनने के दौरान अक्सर कई राज्यों की सीमाओं से गुजरता था। इस बिखराव के कारण कई संरचनात्मक बाधाएँ पैदा हुईं।इसने बड़े पैमाने पर काम करने, आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और आखिरकार मजदूरों की उत्पादकता को सीमित कर दिया।

इसके साथ ही, मल्टी-मॉडल संपर्क में कमियों की वजह से लॉजिस्टिक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रौद्योग्यन के अलग-अलग चरणों के बीच हर बार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या संचालने में अतिरिक्त खर्च और

दुलाई का किराया लगता है। कई चरणों में लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से कुल लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और सामान को तेजी से बाजार तक पहुँचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो आज की रिटेल व्यवस्था में बार-बार ऑर्डर देने वाले साइकल में एक बहुत बड़ी और नुकसानदायक कमी है।

वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी जरूरतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 8% से 10% और औद्योगिक जल प्रदूषण में 20ब है।हजारों छोटी-छोटी और अलग-अलग जगहों पर फैली इकाइयों में नियमों को लागू करना और सही तरीके से प्रबंधन करना पहले एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती रहा है।

इन रुकावटों को व्यवस्थित रूप से दूर करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएममेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना शुरू की, जिसके लिए ?4,445 करोड़ का बजट रखा गया। यह एक अहम कदम था, जो एक ऐसा व्यापक मॉडल पेश करता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों से जुड़े लोगों और निजी साझेदारों के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाती है।

इस योजना के केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी 5एफ फॉर्मूला है यानी फार्म (खेत) से फ़ाइबर (रेशा) से फ़ैबटरी (कारखाना) से फ़ैशन और फ़ारेन (विदेश) तक पहुंच। यह सोच सीधे तौर पर उस बात को सामने लाती है जो भारत को वैश्विक मंच पर अलग बनाती है-हमारी संपूर्ण और बेहद विविध मूल्य श्रृंखला। कच्चे माल के आयात या सिर्फ़ तैयार कपड़ों की बनावट पर निर्भर रहने वाले दूसरे देशों के उलट, भारत वस्त्रों को बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें किसानों के खेतों से लेकर हाई-फ़ैशन रनवे तक की प्रक्रिया शामिल है। इस अनोखी समझ की वजह से, हमारी विकास रणनीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से सामाजिक समानता के बीच एक खास संतुलन बनाने की ज़रूरत है। विस्तार करते समय, हमें हर क्षेत्र के कल्याण का ध्यान रखना होगा, ताकि साधारण किसान और ग्रामीण बुनकर से

लेकर कपड़े के निर्यातक तक, कोई भी पीछे न छूटे। पीएम मित्र परेमवर्क इसी संतुलन को हासिल करता है।

इन पार्कों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे जरूरी बात यह है कि इस नजदीकी से शुरुआत से आखिर तक ट्रैकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य कस्टडी चेन देते हैं। इससे कड़े वैश्विक ईएसजीनियमों का पालन होता है और विदेशों में प्रीमियम कीमत पाने का रास्ता भी बनता है।

1,000 एकड़ से ज्यादा के एक ही इलाके में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग और कपड़ा बनाने की सुविधाओं को एक साथ लाने से अलग-अलग राज्यों के बीच सामान ले जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इससे माल दुलाई का खर्च और ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है और सामान तेजी से बाज़ार तक पहुँच पाता है। समर्पित माल गलियारों और एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण, विदेशी बाज़ारों तक सामान पहुँचाना बहुत सरस्ता और किफायती हो जाता है। हर पार्क में प्लग-एंड-प्ले इंस्टि्टयल इंफ़ास्ट्रक्चर होता है, जिसमें बिजली के खास सब-स्टेशन, लगातार पानी की सप्लाई और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार फ़ैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही, जीरो लिक्विड डिस्कार्ज (जेडएलडी) तकनीक वाले उन्नत एडवांस्ड कॉमन पएल्युट ट्रीटमेंट प्लांट तैयार आधुनिक सुविधाएँ भी होती हैं, जिससे कारोबारियों पर द्वांचगत बोझ कम पड़ता है और कारोबार करने में आसानी होती है।

पीएम मित्र पार्क तेजी से कागजी योजनाओं को असल ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं। इस योजना में सात रणनीतिक पार्क शामिल हैं- पाँच ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट विरुधुनगर (तमिलनाडु), नवसारी (गुजरात), कलबुर्गी (कर्नाटक), धार (मध्य प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और दो

वायुमण्डलीय ट्रैफिक जाम की चपेट में यूरोप

जाता है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि सामान्यतः यह हालात दो-तीन दिन या सप्ताह तक रह सकते हैं पर इस बार यूरोप में यह दौर लंबा चला। इससे इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, जर्मनी सहित यूरोप के करीब 23 देश प्रभावित हैं।

आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी और सिडनी यूनिवर्सिटी की नेचर पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने छह बड़े हीटवेवों का अध्ययन किया है। जलवायु परिवर्तन, नमी बढ़ने, गगनचुंबी इमारतों में तापमान रोधक सामग्री का उपयोग ना के बराबर होने और सुविधा के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अधिक गर्मी बच्चों-बुगुगों के लिए जानलेवा हो जाती है पर इस बार की हीटवेव अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दरअसल, यूरोपवासी इतनी गर्मी के आदी भी नहीं हैं।इसके साथ हीटवेव का असर इतना अधिक है कि शरीर स्वयं अपने आपको तापमान अनुकूल नहीं बना पा रहा है।

यूरोप में हीटवेव के चलते हालात घटने खराब हो गए कि सड़कों की डामर पिटल गई, रेल की पटरियाँ टेडी-मेड़ी हो गईं। इससे हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है। इसके कारण यातायात तक बाधित हो गया है। हीटवेव के कारण जंगलों में आग के समाचार आम हो रहे हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह के चलते चेतावनी जारी की है। यूरोपीय देशों में तापमान 40 सेल्सियस से अधिक पहुंच गया और इससे जनजात बुरी तक प्रभावित हो गया है। देखा जाए तो यूरोप का मौसम संतुलन बिगाड़ गया है।

प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ का परिणाम समूचा विश्व भुगत रहा है। तापमान में बढ़ोतरी वैश्विक है पर यूरोप में इस बार हीटवेव के हालात अधिक गंभीर हो गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो हीटवेव के कारण यूरोप में एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी के हालात बन गए और तेज गर्मी के कारण मौसम जनित बीमारियों और हीटवेव की चपेट में आने से बड़ी संख्या में लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा है।

इन पार्कों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे ज़रूरी बात यह है कि इस नजदीकी से शुरुआत से आखिर तक ट्रैकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य कस्टडी चेन देते हैं। इससे कड़े वैश्विक ईएसजीनियमों का पालन होता है और विदेशों में प्रीमियम कीमत पाने का रास्ता भी बनता है।

ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट वारंगल (तेलंगाना) और अमरावती (महाराष्ट्र) में। अब तक, इस योजना में कुल 69,899 करोड़ के निवेश की दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसमें से 27,658 करोड़ का निवेश पहले ही हो चुका है।

10 मई, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नेतेलगाना के वारंगल में पहले कार्यरत पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया।

इस पार्क में पहले ही ?3,862 करोड़ का निवेश हो चुका है और यहाँ विध-स्तरीय पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है। ये विशेषताएँ स्थायित्व के उन मानकों को दर्शाती हैं, जिन्हें सभी सात पार्क साइटों पर स्थापित किया जा रहा है।

पूरे देश में एक साथ काम शुरू होने से सहकारी संघवाद की तेजी और सफलता दोनों साफ़ दिखती है, जहां सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 100ब जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी भी मिल गई है। पाँच ग्रीनफील्ड साइट्स के लिए जेवीएंग्रीमेंट और एसपीवी पीरी तरह से तैयार हैं, जिससे तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। 2,158 एकड़ में फैले सबसे बड़े पार्क, धार (मध्य प्रदेश) में 2,1436.9 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई गई है। इसी तरह गुजरात (13,084 करोड़), महाराष्ट्र (12,925 करोड़), तमिलनाडु (6,600 करोड़), उत्तर प्रदेश (5,345.8 करोड़) और कर्नाटक (1,700 करोड़) में भी काम को लेकर तेजी देखी गई है। तेजी से हो रहे इस काम के पीछे केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह का सक्रिय

नेतृत्व है। उनके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय अपने कामकाज के तरीकों में तेजी लाया है, मंत्रालय ने प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया है और राज्य सरकारों के साथ अभूतपूर्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है।

लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा बताते हैं, असली पैमाना इसके मानवीय प्रभाव में दिखता है। प्रत्येक पार्क को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

यानी सभी सात स्थलों को मिलाकर, 21 लाख से अधिक औपचारिक आजीविकाएँ हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को अहम सामाजिक-आर्थिक नींव प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक रूप से परिधान निर्माण उद्योग की रीढ़ हैं।

यह व्यापक द्वांचगत प्रयास वस्त्र क्षेत्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण2030 के लिए एक अहम लॉन्गपेंड का काम करता है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350बिलियन डॉलर की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। ऐतिहासिक विखंडन को विश्व स्तरीय, एकीकृत पैमाने से बदलकर करके, पीएम मित्र एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। सशक्त नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हम भारत को वस्त्रों के निर्विवाद, टिकाऊ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)

वैश्विक पटल पर चमकती भारत की शिल्प विरासत

-ओ.पी. पाल

भारत की धरती केवल विविधताओं का देश नहीं बल्कि यह सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का जीवंत कोलाज भी है। कश्मीर के पहाड़ों में बुनी जाने वाली पश्मीना शॉल से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों में पहने जाने वाले मुंडू वस्त्रों तक, बनारस की गलियों की हथकरघा मशीनों से लेकर मध्य प्रदेश के चंदेरी सिल्क तक भारत का हर कोना अपनी विशिष्ट कलात्मक पहचान रखता है। लेकिन, इस बदलते युग में आधुनिक, गतिशील और डिजिटल हो रहे बाजार में इन पारंपरिक शिल्पों के सामने जगह बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को अवसर में बदलने और भारत के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों कारीगरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इंडिया हैंडमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो आज भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए मजबूत डिजिटल इंडिया ब्रिज बन चुका है बल्कि यह वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई पटकथा भी लिख रहा है।

साल 2023 में लॉन्च हुआ यह मंच भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित यह समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल है, जो हमारी पारंपरिक विरासत को संरक्षित कर रहा है। इंडिया हैंडमेड

न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहा है, बल्कि करीब 65 लाख शिल्पी कारीगरों को व्यापक बाजार देकर आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के विजन को भी मजबूत कर रहा है।

‘इंडिया हैंडमेड’ पोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के नारे को धरातल पर सच करता नजर आ रहा है। यह मंच केवल आर्थिक लेन-देन की जगह नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी मजबूत उपकरण है। जब दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति इस पोर्टल से कोई हस्तनिर्मित वस्तु खरीदता है तो वह केवल उत्पाद नहीं खरीद रहा होता बल्कि वह उस भारतीय कारीगर की कल्पना के जादू, उसकी पीढ़ियों की विरासत और भारत की मिट्टी की कहानी को अपने घर ले जा रहा होता है। जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया हैंडमेड यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी प्राचीन कलाएं और तकनीकें पीछे न छूट जाएं।

यह मंच आधुनिकतम ई-कॉमर्स तकनीक और प्राचीनतम मानवीय कौशलों का अद्भुत और सफल संगम है। यह हमारे बुनकरों और शिल्पकारों को केवल जीवित रहने का साधन नहीं दे रहा बल्कि उन्हें सम्मान, वैश्विक पहचान और समृद्धि का नया आसमान दे रहा है। इंडिया

हैंडमेड के माध्यम से भारत की यह अनमोल विरासत न केवल सुरक्षित है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर आजीविका, नवाचार और गौरव का शाश्वत स्रोत बनकर चमक रही है। प्रत्येक भारतीय और वैश्विक नागरिक के लिए इस मंच से जुड़ना भारत की आत्मा और उसकी कलात्मक धड़कन से जुड़ने जैसा है।

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल

भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, कृषि के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। मसलन देश में 71 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों में 64 प्रतिशत महिलाओं की अनुप्राप्त गंभीरता इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत और मजबूत सामाजिक संरचना है। यानी जब एक ग्रामीण महिला बुनकर के बनाए उत्पाद को वैश्विक मंच मिलता है तो वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है बल्कि अपने पूरे परिवार और समुदाय की सामाजिक स्थिति को भी बदल देती है। यही एक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। यह एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया और हैंडमेड (हाथ से बने) उत्पादों के लिए समर्पित है। यहाँ मशीनी या कृत्रिम रूप से तैयार उत्पादों की कोई जगह नहीं है, जिससे हस्तनिर्मित कला की

शुद्धता और प्रामाणिकता बनी रहती है। इंडिया हैंडमेड के माध्यम से अब कारीगर सीधे देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित और पारदर्शी मुआवजा मिलता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले हुनरमंद शिल्पकार के पास पहले केवल स्थानीय मेलों या हाट-बाजारों तक ही पहुंच होती थी। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके उत्पादों को एक विलक पर करोड़ों ग्राहकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनकी बाजार सीमाएं असीमित हो गई हैं।

क्षेत्रीय शिल्पों को अंतरराष्ट्रीय पहचान इंडिया हैंडमेड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रोजमर्रा के उत्पादों के साथ-साथ भारत की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाले शिल्पों को एक वीआईपी स्थान देता है। इसके तहत दो प्रमुख सरकारी पहलों को इस मंच पर विशेष रूप से एकीकृत किया गया है, जिसमें जीआई-टैग और ओडीओपी शामिल हैं। जीआई-टैग किसी उत्पाद की उस विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषताओं को प्रामाणित करता है जो मुख्य रूप से उसके भौगोलिक उद्गम के कारण होती हैं।

इंडिया हैंडमेड पर खरीदार देश के कोने-कोने के प्रामाणिक जीआई उत्पादों को खरीद सकते हैं। इनमें उत्तराखंड की ऐपन कला, कश्मीर की सबसे नरम और बेशकीमती शुद्ध

पश्मीना शॉल, केरल के पारंपरिक सूती वस्त्रों में शुमार मुंडू उत्पाद, यूपी के वाराणसी रेशमी बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साडी (सिल्क उत्पाद), गोरखपुर व अन्य क्षेत्र के मिट्टी से बनी जीवंत मूर्तियां और घरेलू सजावट के सामान टेराकोटा उत्पाद, मध्य प्रदेश की चंदेरी सिल्क, पश्चिम बंगाल की बारीक सूती बुनाई और हाथ से तैयार तंगेल साडी और झारखंड/बिहार के प्राकृतिक सुनहरे रंग और अनूठे टेक्सचर जैसे उत्पाद भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ का हिस्सा बन चुके हैं।

छोटे विक्रेताओं के लिए समावेशी नीतियां भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे अत्यंत कुशल कारीगर हैं जो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं और उनके पास जीएपसटी पंजीकरण नहीं होता। डिजिटल व्यापार में उनके प्रवेश को आसान बनाने के लिए इंडिया हैंडमेड ने एक बेहद प्रगतिशील नियम लागू किया है। वहीं, विशेष नामांकन आईडी सुविधा के तहत छोटे कारीगर या बुनकर जीएपसटी पंजीकृत से छूट दी गई है। वे एक साधारण नामांकन आईडी के साथ खुद को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें अपने गृह राय के भीतर ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति मिलती है। यह कदम देश के सबसे निचले स्तर पर बैठे शिल्पकार को भी डिजिटल कॉमर्स की ताकत से जोड़ता है।

डिजिटल क्रांति की प्रेरक कहानियां देश में इंडिया हैंडमेड जैसे इस मंच के माध्यम से कई शिल्प समूहों और सूक्ष्म उद्यमों की किस्मत बदली है, जो किसी प्रेरक कहानियों से कम नहीं हैं। एक नजर में देखा जाए तो जहां सैटम्स जैसी पहल के तहत लकड़ी की सुंदर नक्काशीदार सजावट, सुगंधित मोमबतियां, कलात्मक टेराकोटा दीये, संगमरमर की मूर्तियां और शानदार हथकरघा साड़ियां जैसी हस्तनिर्मित शिल्पों की गर्माहट को हमारे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन का हिस्सा बना रही है। इसी प्रकार बांस और बेंत को नया जीवन देने की दिशा में खासतौर से उत्तर-पूर्व और भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस और बेंत के काम की एक समृद्ध परंपरा रही है।

दस्ताकार क्राफ्ट इस मंच के जरिए 500 से अधिक स्थानीय कारीगरों के हुनर को सीधे वैश्विक बाजार में ले आया है। इसके अलावा विलेज क्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे कुशल कारीगरों द्वारा बेहद ध्यान और सावधानी से बनाए गए सूती तौलिये, पारंपरिक गमछे और आरामदायक बेडशीट इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी विरासत केवल खाम मीकों पर सजाने के लिए नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को आराम और गुणवत्ता देने के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

नाटो की बैठक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा- पुतिन और जेलेंस्की दोनों यूक्रेन युद्ध का अंत चाहते हैं

एजेंसी वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, दोनों ही यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता में जितनी प्रगति लोगों को दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा आगे बात बढ़ चुकी है। व्हट्ट हाउस में 'ट्रंप अकाउंटेंस' निवेश कार्यक्रम शुरू करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल ही में उनकी पुतिन से 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि उनसे बात करने के बाद भी पुतिन सैन्य हमले क्यों जारी रखे हुए हैं, तो ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि उन पर दबाव है। वह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और यूक्रेन भी इसे खत्म करना चाहता है। हमारी बातचीत चल रही है, और देखते हैं कि क्या हम इसे खत्म कर पाते हैं।" लगातार जारी लड़ाई के बावजूद ट्रंप ने भरोसा जताया कि हालात सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम लोग जितना समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब इसे खत्म करना चाहते हैं।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बहरीन के राजा के साथ अहम बैठक, सहयोग बढ़ाने पर जोर

पनामा। भारत और बहरीन के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बहरीन राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत के विदेश मंत्री (इंएएम) एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही काउन्सिल ऑफ़ प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। भारत-बहरीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बहरीन के राजा के लगातार मार्गदर्शन की हम दिल से सराहना करते हैं। बहरीन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भी उनका धन्यवाद किया।" जयशंकर ने बताया कि इस दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इससे पहले विदेश मंत्री (इंएएम) एस. जयशंकर ने बहरीन के मनानाम में अपने समकक्ष अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में चल रहे हालात पर चर्चा की।

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में पुलिस चौकी पर हमला, दो एसएचओ समेत नौ जवान और 15 आतंकी मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान के जियारत जिले में सोमवार देररात एक पुलिस चौकी पर हुए हमले में दो थाना प्रभारी (एसएचओ) समेत नौ पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इस घटना के बाद शुरू किए गए संयुक्त सुरक्षा अभियान में 15 आतंकी मारे गए। हमलावार पांच पुलिस कर्मचारियों को अगवा कर अपने साथ ले गए हैं। जियारत के पुलिस अधीक्षक अब्दुल कुदूस के अनुसार हमलावरों ने कच मांगी फेज तीन इलाके में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। जियो न्यूज चैनल और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों में मांगी के थाना प्रभारी मोहम्मद हुसैन और कोवास के थाना प्रभारी सोहबत खान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों के बीच रातभर जबदस्त गोलीबारी होती रही। जवानों के शवों को जियारत के जिला मुख्यालय स्थलात ले जाया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शाहिद रिद ने कहा कि जियारत जिले के मांगी इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पूरा कर लिया गया है। इस अभियान में 15 आतंकी मारे गए। इस अभियान में फ्रंटियर कॉर्प्स, बलोचिस्तान पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ऑपरेशन्स विंग और एंटी-टेररिज्म फ़ोर्स ने हिस्सा लिया।

नेपाल-कंबोडिया मानव तस्करी और साइबर अपराध के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग

काठमांडू। नेपाल और कंबोडिया मानव तस्करी, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी (स्कैम) अभियानों के खिलाफ आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। कंबोडिया के प्रोम पेन्ह में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के दौरान नेपाल के राजदूत धन बहादुर ओली ने कंबोडिया के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय की स्थायी राज्य सचिव ईट सोफिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर संघटित अपराध से निपटने, खुफिया व सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने और संस्थागत क्षमता के निर्माण के लिए संबन्धित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नेपाली दूतावास के अनुसार राजदूत ओली ने कंबोडिया में चल रहे ऑनलाइन स्कैम सेंटरों से नेपाली नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए कंबोडिया की शाही सरकार को धन्यवाद दिया।

भीषण गर्मी के बीच पुर्तगाल में हर साल जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र चार गुना बढ़ा

एजेंसी लिस्बन । आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुर्तगाल में जंगल की आग से जला हुआ क्षेत्र पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग चार गुना बढ़ गया है। भीषण गर्मी और आग लगने के बड़े हुए खतरे के कारण देशभर में ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है। पुर्तगाल के ग्रामीण अंग्रे एकिकृत प्रबंधन प्रणाली (एसजीआईएफआर) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक देशभर में जंगल में आग लगने की 4,592 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 30,155 हेक्टेयर क्षेत्र जल चुका है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कुल जला हुआ क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा केवल बुधवार से रविवार के बीच दर्ज किया गया। 2025 की इसी अवधि की तुलना में इस साल जला हुआ क्षेत्र लगभग चार गुना बढ़ गया है, जो 2017 के बाद इस



अवधि के लिए सबसे अधिक है। वहीं, जंगल में आग लगने की घटनाओं की संख्या में भी पिछले साल की तुलना में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 2022

एआई, एयरोस्पेस और निवेश में भारत के साथ मजबूत संबंधों पर क्यूबेक की नजर : मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट

एजेंसी जकार्ता । कनाडा के क्यूबेक प्रांत के मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट के अनुसार, क्यूबेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एयरोस्पेस, शिक्षा और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को भी बढ़ावा देने की योजना है। न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत में क्यूबेक के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं ला फ्रैंकोफोनी मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट ने कहा कि प्रांत अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और भारत के साथ दीर्घकालिक तथा स्थिर साझेदारी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित



कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और भारत के साथ स्थायी संबंध स्थापित करने का

धमकियों के बीच वार्ता संभव नहीं, अमेरिका करे समझौते का सम्मान : विदेश मंत्री अराघची

एजेंसी तेहरान। मध्य-पूर्व एशिया में फिलहाल शांति है, लेकिन यूएस-ईरान के बीच हाल ही में हुआ समझौता कितने दिन तक कायम रहेगा, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। इसकी एक अहम वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर ईरान की ओर से दिए जा रहे जवाब माने जा रहे हैं। भी ट्रंप ने ऐसा ही कुछ कहा, जिसका जवाब ईरान की ओर से आया। ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि धमकियों से काम नहीं चलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि यदि धमकियों का सिलसिला जारी रहा, तो अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने इस संबंध में अमेरिका के साथ हुए समझौता जपान (एमओयू) के पैराग्राफ 13 का हवाला दिया। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म



सेनाएं किसी भी तरह की धमकियों से प्रभावित होंगी। अपने हस्ताक्षर का सम्मान करें। ' अराघची की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका या तो ईरान के साथ समझौता करेगा या फिर 'काम तमाम करेगा' । ट्रंप के मुताबिक या

ऐसे क्षेत्र बताया, जिनमें सहयोग की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि क्यूबेक और भारत के विश्वविद्यालयों के बीच पहले से मजबूत तालमेल है, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'एयरोस्पेस एक बेहتریन क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और शिक्षा भी। हमारे विश्वविद्यालयों के बीच काफी करीबी सहयोग है, जिसे और मजबूत करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और सुरक्षित सप्लाई चेन तथा भरोसेमंद साझेदारियां विकसित करने के लिए देशों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। उनके अनुसार, भारत और क्यूबेक इस दिशा में प्रभावी साझेदारी कर सकते हैं। क्यूबेक में

निवेश और कारोबार के अवसर तलाशने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करते हुए स्कीट ने कहा कि यह प्रांत उद्यमिता और नवाचार आधारित व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा, 'भारतीय निवेशकों के लिए यहां अनेक अवसर हैं। हमें भारतीय उद्यमियों की सोच और उद्यमिता का अनुभव पसंद है। भारतीय कंपनियों के लिए क्यूबेक में निवेश और कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं, वहीं क्यूबेक की कंपनियों के लिए भारत में भी व्यापक अवसर मौजूद हैं।' उन्होंने कहा कि क्यूबेक भारत में अपनी उपस्थिति और मजबूत करना चाहता है, ताकि दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

सीरिया की राजधानी दमिश्क में धमाका, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के दौरान होलट के पास हुआ विस्फोट

एजेंसी दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दौरे के दौरान एक जंगल विस्फोट हुआ। यह धमाका उस होलट के नजदीक हुआ, जहां मैक्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हकत में आ गईं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनीं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घटनास्थल के आसपास धुएं का गुबार उठा दिखाई दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। विस्फोट के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने होलट और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात रोक दिया गया और सुरक्षा जांच तेज कर दी गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर हाथ है।गौरतलब है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद दमिश्क का दौरा करने वाले यूरोपीय संघ (E) के पहले प्रमुख नेता हैं। ऐसे



रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट दुर्घटनावाश हुआ या इसके पीछे किसी साजिश का

में उनके दौरे के दौरान हुआ यह धमाका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है।

अमेरिका में हीट वेव का कहर, 250वीं वर्षगांठ के सप्ताहांत में कई लोगों की मौत

एजेंसी न्यूयॉर्क । अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न वाले सप्ताहांत के दौरान देश के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाली हीट वेव की लहर ने पूर्वी तट, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक लोगों की जान ले ली। अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में हीट वेव की लहर के कारण कम से कम 29 लोगों की मौत होने का अनुमान है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ये मौतें 10 कार्टोटियों में दर्ज की गईं। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मृतक ऐसे घरों में पाए गए, जहां एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं थी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यू जर्सी के स्वास्थ्य आयुक्त रेनाडो वाशिंगटन ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मृतकों में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कुछ युवा वयस्क भी शामिल हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू जर्सी की गवर्नर मिर्की

शेरिल ने कहा, 'अमेरिका में मौसम से जुड़ी मौतों का सबसे बड़ा कारण भीषण गर्मी है और पिछले 14 वर्षों में यह सबसे लंबा और सबसे तीव्र गर्मी का दौर है।' फॉक्स फोकास्ट सेंटर के अनुसार, इस हीट वेव की लहर ने अमेरिका के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। 20 से अधिक राज्यों में तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। 30 जून से 5 जुलाई (रविवार) के बीच दैनिक अधिकतम तापमान के कम से कम 148 नए रिकॉर्ड बने।शिकागो में हालिया गर्मी की लहर से जुड़ी वजहों से चार लोगों की मौत हुई। यह जानकारी कुक काउंटी मेडिकल एग्जामिनेर कार्यालय के रिकॉर्ड से मिली है। मिसिसिपी के हिंड्स काउंटी के अधिकारियों ने शनिवार को पुष्टि की कि 83 वर्षीय एक महिला की अपने घर के पास बगीचे में गिरने के बाद अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से मौत हो गई।

चीन की मिसाइल परीक्षण ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता, कहा- बीजिंग का तेजी से परमाणु हथियार बनाना परेशानी की बात

एजेंसी वाशिंगटन । चीन ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में सबमरीन से लॉन्च वाली इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका ने चीन के इस टेस्टिंग को लेकर भारी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि बीजिंग का बढ़ता परमाणु हथियार, परमाणु प्रसार को रोकने की दुनिया भर की कोशिशों के खिलाफ है। राज्य विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगांट ने कहा कि चीन के एक सबमरीन से बिना हथियार वाली इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने पर अमेरिका की नजर थी, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरी। पिगांट ने कहा, 'ऐसे समय में जब अमेरिका परमाणु प्रसार को रोकने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है, चीन इसका उल्टा कर रहा है।'



में चीन से अपील की गई कि वह हथियार नियंत्रण पर औपचारिक बातचीत करे और लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च के बारे में पारदर्शिता बढ़ाए। पिगांट ने कहा, 'हम चीन से लगातार अपील करते हैं कि वह काम की हथियार नियंत्रण बातचीत में

शामिल हो और सभी इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेस लॉन्च के लिए एक रेगुलर नोटिफिकेशन अरेंजमेंट शुरू करे, जैसा कि बाकी सभी पी5 सदस्यों ने किया है।' अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में अपने सुरक्षा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। बयान में आगे कहा गया, 'अमेरिका अपने साधियों और साझेदारों के प्रति अपने रक्षा प्रतिबद्धता पर अडिग

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिस्टोफरेंसी को लेकर कहा- यह बड़ा उद्योग है और अमेरिका को इस पर हावी होना चाहिए

एजेंसी वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टोफरेंसी को एक रणनीतिक उद्योग बताया, जिस पर अमेरिका को हावी होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि डिजिटल एसेट्स को अपनाने में नाकाम रहने पर चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वित्तीय क्षेत्रों में से एक में सबसे आगे हो जाएगा। ट्रंप अकाउंटेंस प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर व्हट्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने क्रिस्टोफरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस रखा और दोनों को अमेरिका के आर्थिक और तकनीकी भविष्य के लिए जरूरी बताया। ट्रंप ने कहा, 'मैं सिर्फ एक वजह से क्रिस्टो का बड़ा समर्थक हूँ: अगर यह हमारे पास नहीं

है, तो चीन के पास होगा और वे इसे पाना चाहेंगे। लेकिन अब वे इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्रिस्टो पर कब्जा कर लिया है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल एसेट्स पर उनके विचार समय के साथ बदले हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इसका फैसलें हूँ; शुरू में नहीं था, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। अपने पहले कार्यकाल में मैं सच में नहीं था, लेकिन मैं देखता था और मैंने इसे बढ़ते देखा। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है।' ट्रंप ने कहा कि भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन ने इस क्षेत्र के लिए उनके समर्थन को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, 'अगर हम ऐसा नहीं करते, तो चीन एक मिनट में ऐसा कर देता। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। बीजिंग

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर के बेटे जयवीर देउबा को आय से अधिक संपत्ति मामले में सात दिन के भीतर उपस्थित होने का नोटिस

एजेंसी काठमांडू। नेपाल के मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति और पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के पुत्र जयवीर देउबा को सात दिन के भीतर विभाग में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति (मनी लॉन्ड्रिंग) संबंधी



जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्टीकरण और जानकारी प्राप्त करनी है। इसी उद्देश्य से जयवीर देउबा को नोटिस मिलने की तारीख से सात दिनों के भीतर विभाग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस देउबा परिवार के बुदानीलकण्ठ स्विट्स आवास पर चरपा किया गया है। इससे पहले विभाग पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू रणगा देउबा को भी पृष्ठछाछ के लिए बुला चुका है। हालांकि, आरजू ने विभाग को सूचित किया है कि वे उपस्थित होकर अंततः तम विभाग में सविनय होकर अव्यक्त जानकारी और स्पष्टीकरण देंगी।

हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में मिले विशेष स्वागत का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। वीडियो के साथ



उन्होंने लिखा, 'कल शाम जकार्ता में हुए खास स्वागत की खास बातें। आज राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत का इंतजार है।' इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए स्कूली बच्चे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लेकर उनके पहुंचे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने उनके पास जाकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सरेमोनियल रिसेप्शन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुबियांतो ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर

उन्का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात की और फिर राष्ट्रपति सुबियांतो ने भी मारतीय प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्ताना मर्डेका (राष्ट्रपति महल) में गैस्ट बुक पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। बैठक से पहले पीएम मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे।

एजेंसी जकार्ता । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग, रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। साथ ही मई 2018 में

स्थापित भारत-इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा होने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि दोनों नेता इस दौर के दौरान प्रम्बानन मंदिर परिसर में रेस्टोरेशन का काम शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत में मर्डेका पैलेस (इंडोनेशिया का प्रिंसिपैलियल पैलेस) में सरेमोनियल रिसेप्शन का आयोजन किया गया। आज दोनों देशों के बीच कई एमओयू और द्विपक्षीय समझौतों पर

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



कटुआ, 07 जुलाई (हि.स.)। सरकारी डिग्री कॉलेज महानपुर में चल रहे 100 दिवस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य नशामुक्त व स्वस्थ समाज का संदेश फैलाना रहा। कार्यक्रम का आयोजन भौतिक विभागाध्यक्ष प्रो. बिती

शर्मा ने प्राचार्य डॉ. संगीता सुदन के मार्गदर्शन में किया। प्रो. शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जागरूकता सत्र में से नो टू ड्रग्स नारा अभियान, निबंध लेखन प्रतियोगिता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें स्टाफ, छात्र एवं आसपास के श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता और पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. रूपाणी जसरोटिया, किशोरी लाल, रमेश लाल, कुलदीप, सनी, अनु व अनु राधा सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

बाबरी के चंदे और मदरसों के कदाचार पर भी बोल दें अखिलेश, वोट बैंक हो जाएगा नाराज : ब्रजेश पाठक

राममंदिर चढ़ावा विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा पलटवार



अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाला बताया। पाठक ने कहा कि सपा और कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि वे मदरसों में चल रहे कदाचारों पर सवाल उठा सकें। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर एसआईटी जांच का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्सेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण पर एसआईटी जांच चल रही है। कोई भी दोषी बचे न और कड़ी कार्रवाई हो, यह सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सनातन संस्कृति की पताका को और चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस और अन्य दल राम मंदिर चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद सहित मुरिलिम

कहा- तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते राममंदिर को टारगेट कर रहा विपक्ष
कदाचार का केंद्र बन चुके हैं कई मदरसे, मगर सपा-कांग्रेस कभी नहीं उठाते सवाल
राममंदिर मामले में एसआईटी कर रही जांच, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा
सनातन संस्कृति की पताका को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

लखनऊ, 07 जुलाई उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को

प्रतिष्ठानों, मस्जिदों या मदरसों के चंदे और कदाचार पर कभी सवाल नहीं उठाते। पाठक ने कहा कि कई मदरसों की हालत ये है कि वे कदाचार के अड्डे बने हुए हैं। मगर, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई है और कानून के अनुसार कार्रवाई हो, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है।

उधमपुर में नाबार्ड-आरआईडीएफ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश

उधमपुर, 07 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक में मुख्य योजना अधिकारी उत्तम सिंह तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) डॉ. सिद्धार्थ ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही आरआईडीएफ परियोजनाओं की विस्तृत प्रगति से अवगत



कराया। परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने तथा सभी बाधाओं को दूर कर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया। उपायुक्त ने कार्यान्वयन एजेंसियों को संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने, परियोजनाओं की स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराने तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जा सकें।

राष्ट्र सेविका समिति जम्मू द्वारा पथ संचलन का आयोजन

जम्मू, जुलाई 07। राष्ट्र सेविका समिति, जम्मू कश्मीर की जम्मू संभाग की नारी शक्ति ने गत सायंकल जन जागरण हेतु जम्मू नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पथ संचलन में भाग लिया। पथ संचलन का आयोजन राष्ट्रवाद, अनुशासन, संस्कृति और परंपरा, सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में किया गया। नागरिकों के बीच राष्ट्र प्रथम के बोध का प्रचार प्रसार करना पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य रहा। पथ संचलन से पूर्व बताया गया कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपराओं में से एक है। इसकी अवस्था बड़ी विशेषता विविधता में एकता है। अलग-अलग भाषाएँ, रीति-रिवाज, पूजा-पद्धतियाँ और परंपराएँ होने के बावजूद हमारा समाज कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों से जुड़ा है जो उसे एक सूत्र में बाँधते हैं। इनमें धर्म, कर्म और गौ के प्रति श्रद्धा का विशेष स्थान है। धर्म का अर्थ केवल किसी संप्रदाय या पूजा-पद्धति से नहीं है। धर्म वह व्यवस्था है जो सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और लोककल्याण का मार्ग दिखाती है। सनातन परंपरा में धर्म का पालन व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास का आधार माना गया है। जब समाज धर्म के सिद्धांतों पर चलता है, तब आपसी विश्वास,



सहयोग और सद्भाव मजबूत होते हैं। धर्म सनातन दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। भगवद्गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को जिम्मेदार, अनुशासित और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यही भावना समाज को सशक्त और संगठित बनाती है। गौ भारतीय संस्कृति में करुणा, सेवा और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। प्राचीन काल से कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डोडा में मलेरिया टीम ने चलाया डेगू जागरूकता एवं निगरानी अभियान

डोडा, 07 जुलाई। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत चल रहे एटी डेगू माह अभियान के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय डोडा की जिला मलेरिया टीम ने डोडा शहर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता एवं निगरानी अभियान चलाया।



अभियान के दौरान टीम ने सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी/बीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से लोगों को डेगू और मलेरिया से बचाव एवं नियंत्रण के बारे में जागरूक किया। लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने, घरों के आसपास जमा पानी को हटाने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। निगरानी अभियान के तहत टीम ने सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा से सबद्ध अस्पताल के पैथोलॉजी

अनुभाग में रखे गए एमएफ-8 रजिस्टर का भी निरीक्षण किया, ताकि कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की सही व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यह अभियान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डोडा डॉ. विनोद शर्मा के मार्गदर्शन तथा जिला मलेरिया अधिकारी डोडा की निगरानी में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया, ताकि जिले में मच्छर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

किश्तवाड़ के पाट्टर में सड़क सुरक्षा एवं वाहन फिटनेस अभियान आयोजित

किश्तवाड़, 07 जुलाई। उपायुक्त किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा के निर्देशों तथा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तस्लीम जावेद की निगरानी में मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़ ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से पाट्टर क्षेत्र में व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं वाहन फिटनेस अभियान चलाया। अभियान एसडीपीओ पाट्टर विजय भगत, थाना प्रभारी पाट्टर अमृत कटोच तथा मोटर वाहन निरीक्षक रोबिन परिहार की मौजूदगी में आयोजित किया गया। अभियान का संदेश था— फ़सुरक्षित वाहन ज जिम्मेदार चालक ज सुरक्षित यात्रा। फ़सुरक्षित सड़क सुरक्षा सबकी साझा जिम्मेदारी है—आइए, मिलकर जीवन बचाए। अभियान के दौरान वाहनों की तकनीकी जांच कर उनकी सड़क पर चलने की उपयुक्तता तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुपालन की जांच की गई। केवल उन्हीं वाहनों पर सड़क सुरक्षा अनुपालन स्टिकर लगाए गए, जो तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट पाए गए और जिनके पास सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध थे।

कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत

जम्मू, 07 जुलाई (हि.स.)। मंगलवार को जम्मू जिले के अखनूर के चोकी चौरा इलाके में एक कार खाई में गिर गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना राजमार्ग पर हुई जब पंजीकरण संख्या जेके 11ए 4854 वाली एक कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। मृतक की पहचान राजु शर्मा पुत्र देव राज निवासी कालाकोट के रूप में हुई है। इस दुर्घटना में दो यात्री घायल हो गए। उनकी पहचान रोशन लाल पुत्र शाम लाल निवासी कांगरी बरीपट्टन और तुषार रैना पुत्र मदन लाल निवासी कालाकोट के रूप में हुई है। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कल्याण एवं अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में SABLO द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त



लुधियाना, 06 जुलाई। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स ऑर्गेनाइजेशन (SABLO), जो श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा में लगे यात्रियों तथा भंडारा (लंगर) सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ने यात्रियों द्वारा झेली जा रही अनेक कठिनाइयों पर गंभीर चिंता एवं गहरा दुःख व्यक्त किया है। संगठन ने विशेष रूप से पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कल्याण, गरिमा तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित गंभीर मुद्दों/चिंताओं को उजागर किया है। SABLO ने श्राद्ध बोर्ड तथा अन्य सभी संबंधित/सक्षम प्राधिकरणों से आग्रह किया है कि वे तत्काल एवं प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाएँ ताकि प्रत्येक श्रद्धालु को संपूर्ण यात्रा के दौरान सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। SABLO ने विभिन्न ट्रॉजिक प्वाइंट्स, विशेषकर जम्मू तथा बालटाल एवं नुनवान स्थित आधार शिविरों पर श्रद्धालुओं को कथित रूप से हो रही कठिनाइयों के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए श्री अमरनाथ जी श्राद्ध बोर्ड को एक अत्यंत आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संगठन के अध्यक्ष श्री राजन गुप्ता ने श्राद्ध बोर्ड

का ध्यान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित हो रही अनेक रिपोर्टों, वीडियो एवं समाचारों की ओर आकर्षित किया है, जिनसे संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को कथित रूप से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए विवश होना पड़ा है, जो कुछ मामलों में 24 से 48 घंटे अथवा उससे भी अधिक रही है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि अनेक स्थानों पर, जहाँ श्रद्धालुओं को रुकना पड़ता है, वहीं भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्नान सुविधाएँ, शौचालय, चिकित्सा सहायता तथा अस्थायी आवास की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। संगठन ने उन रिपोर्टों पर भी चिंता व्यक्त की है जिनमें श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज एवं अन्य कठोर उपाय अपनाए जाने का आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि यदि ऐसी घटनाएँ हुई हैं, तो वे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं तथा पवित्र यात्रा की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। श्री राजन गुप्ता ने इस बात पर बल दिया कि देश के प्रत्येक कोने से—जिसमें दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम तथा अनेक अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं—लाखों श्रद्धालु केवल भगवान श्री अमरनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस कठिन एवं दुर्गम यात्रा को करते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे उसकी आयु, लिंग अथवा निवास स्थान कुछ भी हो, यात्रा के दौरान करुणा, शिष्टाचार, सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकारी है। संगठन के श्री फकीर चंद वर्मा ने कहा कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, कल्याण, सुविधा एवं गरिमा सुनिश्चित करना श्री अमरनाथ जी श्राद्ध बोर्ड की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, जिसे नागरिक प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ निकट समन्वय में

निभाया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित प्राधिकरणों से आग्रह किया कि वर्तमान व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा की जाए तथा जहाँ कहीं भी कोई कमी या त्रुटि पाई जाए, वहाँ बिना विलंब आवश्यक सुधारालाभक कदम उठाए जाएं। संगठन के मीडिया सचिव श्री पंकज सोनी ने श्राद्ध बोर्ड से आग्रह किया है कि सभी ट्रॉजिक प्वाइंट्स पर भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं तथा अस्थायी आवास की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए; मानवीय एवं श्रद्धालु-अनुकूल भौंड प्रबंधन व्यवस्था अपनाई जाए; श्रद्धालुओं को अनावश्यक कठिनाइयों अथवा उन्नीडन से बचाया जाए; 24x7 निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए; निरंतर पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख ट्रॉजिक प्वाइंट्स पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाए; आपातकालीन संपर्क विवरण एवं सहायता केंद्र (हेल्प डेस्क) संबंधी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए; सभी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए; तथा जहाँ कहीं भी श्रद्धालुओं के कल्याण अथवा गरिमा को प्रभावित करने वाली गंभीर कमियाँ पाई जाएँ, वहीं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। संगठन के वित्त सचिव श्री विजय मेहरा ने भी आग्रह किया है कि जीवन एवं जन-सुरक्षा की रक्षा हेतु पूर्णतः अपरिहार्य एवं अत्यंत विरल परिस्थितियों को छोड़कर, शांतिपूर्ण श्रद्धालुओं के विरुद्ध लाठीचार्ज अथवा किसी भी प्रकार की बलपूर्वक अथवा दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। श्री राजन गुप्ता ने अनुरोध किया है कि इस प्रतिवेदन को अत्यंत आवश्यक मानते हुए सभी संबंधित प्राधिकरणों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ तथा उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला आयुष सोसायटी की पहली बैठक, एडीडीसी ने आयुष सेवाओं व आधारभूत ढांचे की समीक्षा की



कटुआ, 07 जुलाई (हि.स.)। जिला आयुष सोसायटी की पहली बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुरेंद्र मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें जिले में आयुष संस्थानों के कार्य, आधारभूत ढांचे के विकास और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला आयुष अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय रैना, सहायक आयुक्त विकास अखिल सदोत्रा, जिला पंचायत

अधिकारी आमिर चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि जिले में 57 आयुष संस्थानों जिनमें 42 आयुष आरोग्य मंदिर शामिल हैं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बैठक में आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत योग और सुप्रजा, योग मित्र, आयुष रिवाज व कारुण्य जैसी आयुर्वेदिक योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। साथ ही जीएमसी कटुआ में विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। आधारभूत ढांचे की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बिलावर के मंडली में 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल लगभग तैयार है और इसे सितंबर तक जनता को समर्पित किया जाएगा जबकि भनोड में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य जारी है। एडीडीसी ने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।